



डिजिटल तकनीक से सशक्त छत्तीसगढ़

डिजिटल छत्तीसगढ़

तकनीक, पारदर्शिता और सुशासन का नया अध्याय

सेवा सेतु से भारतनेट तक, ई-ऑफिस से डिजिटल ग्राम तक... तकनीक के सहारे बदल रही शासन की तस्वीर



“ डिजिटल तकनीक केवल सुविधाओं का माध्यम नहीं, बल्कि सुशासन की सबसे प्रभावी शक्ति है। हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, समयबद्ध और सहज सेवाएं उपलब्ध हों। सेवा सेतु, ई-ऑफिस, भारतनेट, डिजिटल सेवा केंद्र और अन्य ई-गवर्नेंस पहलें इसी दिशा में मजबूत कदम हैं। तकनीक के माध्यम से शासन को नागरिकों के और करीब लाना तथा गांव-गांव तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ डिजिटल नवाचार और नागरिक-केंद्रित प्रशासन का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरेगा।

– विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ ”

वर्ष 2026 का छत्तीसगढ़ केवल भौतिक विकास की नहीं, बल्कि डिजिटल परिवर्तन की भी एक नई कहानी लिख रहा है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, नागरिक सेवाओं में सरलता और तकनीक आधारित सुशासन को केंद्र में रखकर राज्य ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज सरकारी सेवाएं नागरिकों तक पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और सहज तरीके से पहुंच रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन सेवाएं, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, ई-ऑफिस व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने वाली परियोजनाएं मिलकर एक ऐसे छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रही हैं, जहां शासन और जनता के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है।



सेवा सेतु : नागरिक सेवाओं का सबसे बड़ा डिजिटल द्वार

छत्तीसगढ़ की डिजिटल यात्रा में 'सेवा सेतु' एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनकर उभरा है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत स्वरूप के रूप में विकसित यह प्लेटफॉर्म आज राज्य की 441 से अधिक शासकीय सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को एक ही मंच पर उपलब्ध करा रहा है। आय, जाति, निवास, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन सहित विभिन्न प्रमाण-पत्रों और सेवाओं के लिए अब नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति की निगरानी और डिजिटल प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा ने सेवा वितरण को पूरी तरह बदल दिया है। सेवा सेतु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाण, उमंग, व्हाट्सएप इंटरफेस और भाषिणी जैसी आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है। नागरिक अब व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा सेवा की स्थिति की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध यह पोर्टल तकनीक को आमजन की भाषा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण प्रयास है।



घर बैठे आवेदन, ट्रैकिंग और डिजिटल प्रमाण-पत्र की सुविधा



ई-ऑफिस : कागज से क्लिक तक प्रशासन की यात्रा

शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को तेजी से लागू किया गया है। मंत्रालय से लेकर विभागीय कार्यालयों तक फाइलों का डिजिटल संचालन प्रशासनिक कार्यों में नई गति लेकर आया है। ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव हुई है। निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है, दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ी है। शासन का लक्ष्य सभी विभागों और जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस का पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।



माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
श्री विष्णु देव साय
के कर कमलों से
ई-ऑफिस
ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ
दिनांक - 21 अगस्त 2024
पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध प्रशासन



स्वागतम और सीएमओ पोर्टल : सरकार और जनता के बीच मजबूत डिजिटल सेतु

डिजिटल गवर्नेंस को नागरिकों के और करीब लाने के लिए स्वागतम पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। स्वागतम पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय आने वाले नागरिक अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर संबंधित अधिकारियों से आसानी से मिल सकते हैं। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुरक्षित बनी है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल राज्य की योजनाओं, जनहितकारी निर्णयों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी नागरिकों तक एक क्लिक में पहुंचा रहा है।



महानदी भवन, नवा रायपुर
पारदर्शिता, सुरक्षा और सुगम पहुँच



भारतनेट : गांव-गांव पहुंच रही डिजिटल क्रांति

डिजिटल छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव डिजिटल कनेक्टिविटी है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित नेटवर्क से जोड़ने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 3,942 करोड़ रुपये की इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में तेज और विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, टेलीमैडिसिन और ग्रामीण उद्यमिता को नई ताकत मिलेगी। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डिजिटल समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



11,682 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल पहुंच



अटल डिजिटल सुविधा केंद्र : गांवों तक पहुंची डिजिटल सेवाएं

डिजिटल बदलाव का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है, जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के साथ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं, प्रमाण-पत्रों, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों का समय और खर्च दोनों बच रहे हैं।



समय और खर्च की बचत, सुविधाएं आपके पास



डीबीटी और डिजिटल भुगतान : पारदर्शिता का मजबूत आधार

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से शासकीय योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। भुगतान की रीयल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल रसीद और ऑनलाइन सत्यापन जैसी सुविधाओं ने पारदर्शिता को और मजबूत किया है। ट्रेजरी और ई-चालान के एकीकरण से नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे सेवाओं का उपयोग अधिक सरल और सुरक्षित हुआ है।



सीधे खाते में राशि, पारदर्शी लेनदेन



तकनीक से मजबूत हो रही जवाबदेही

- लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय-सीमा सुनिश्चित
- ऑटोमैटिक पेनल्टी केलकुलेशन और स्वतः शिकायत पंजीकरण
- व्यूअर कोड आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन
- डिजिटल सिग्नेचर, क्लाउड स्टोरेज, रीयल टाइम डैशबोर्ड
- एमआईएस रिपोर्टिंग से बेहतर मॉनिटरिंग
- जनता को त्वरित, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाएं





डिजिटल सुशासन की नई पहचान



441+ शासकीय सेवाएं एक मंच पर



22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध पोर्टल



11,682 ग्राम पंचायतें भारतनेट से जुड़ेगी



3.2 करोड़+ ग्राम पंचायतें भारतनेट से जुड़ेगी

डिजिटल तकनीक के साथ आगे बढ़ता छत्तीसगढ़... पारदर्शी शासन, त्वरित सेवाएं और सशक्त नागरिकता की नई तस्वीर।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्र, समाज और सनातन संस्कृति के प्रति दिलीप सिंह जुदेव का समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा : मुख्यमंत्री साय



को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में श्रद्धेय स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव जी की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया और राष्ट्र एवं समाज के प्रति उनके योगदान का स्मरण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र, समाज और सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित रहा। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा, उनके स्वाभिमान और सामाजिक जागरण के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें जन-जन के हृदय में विशिष्ट स्थान दिलाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्री जुदेव जी का छत्तीसगढ़ की माटी और यहां के लोगों से गहरा आत्मीय जुड़ाव था। विशेष रूप से जनजातीय अंचलों में उन्होंने समाज को संगठित करने, लोगों में आत्मविश्वास जगाने और उनकी आवाज को मजबूती देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री जुदेव जी का जीवन राष्ट्रसेवा, सामाजिक सरोकार और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति अटूट निष्ठा का प्रेरक उदाहरण है। उनके विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को समाज एवं राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे। इस अवसर पर श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रियंवदा सिंह जुदेव, प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी तथा छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा उपस्थित थे।

ब्रश नहीं करते राहुल गांधी, नहीं तो बोलने में आती शुद्धता : विधायक पुरंदर मिश्रा



रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वह एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह ब्रश नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो उनकी बोली में शुद्धता आएगी। यह बयान उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दिए गए टिप्पणी को लेकर दिया है। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी शोभनीय नहीं है। वह संविधान की बात करते हैं, पीएम मोदी उनके भी प्रधानमंत्री है, ऐसी टिपपणी करना दुखद है। विभाजन विभीषिका दिवस मनाने को लेकर पुरंदर मिश्रा ने कहा कि 14 अगस्त दुःखद तारीख है। इस दिन स्वार्थी और असामाजिक तत्वों ने भारत का विभाजन किया। विभाजन करने वाले आज दुःख भोग रहे हैं और उनकी पार्टी भी दुःख भोग रही है।

राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर सारागांव में निकाली स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में तिरंगा यात्राओं और हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से लोगों को राष्ट्रप्रेम, राष्टीय एकता और नागरिक जिम्मेदारी का संदेश दिया जा रहा है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य केवल हाथों में राष्टीय ध्वज लेकर रैली निकालना नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष और बलिदानों को याद करना, तिरंगे के प्रति सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना तथा देश की एकता और अखंडता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आजादी के बाद तिरंगा देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और गौरव का प्रतीक बन गया। इसी भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता दिवस के आसपास हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

राज्यपाल ने 12 वर्षीय छात्र मास्टर दिव्यांश की पुस्तक ‘थॉट्स अबाउट गॉड’ का किया विमोचन

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने शुक्रवार को रायपुर के 12 वर्षीय छात्र मास्टर दिव्यांश सुलतानिया द्वारा लिखित पुस्तक ‘थॉट्स अबाउट गॉड’ का विमोचन किया। उन्होंने दिव्यांश के रचनात्मक प्रयास की सराहना करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। दिव्यांश ने अपने दादा की प्रेरणा से इस पुस्तक की रचना की है। पुस्तक में एक युवा छात्र के दृष्टिकोण से ईश्वर और आध्यात्मिकता से जुड़े विचारों, सवालों और उसकी अपनी समझ को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है। कम उम्र में गंभीर और विचारपरक विषय पर पुस्तक



लिखने के दिव्यांश के प्रयास को राज्यपाल ने सराहनीय बताया। इस अवसर पर राज्यपाल ने मास्टर दिव्यांश की दूसरी पुस्तक ‘फॉम पोकेट मनी टू पोर्टफोलियो’ के कवर को भी

उप मुख्यमंत्री साव ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, 14 गांवों में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, गूंजा देशभक्ति का जयघोष

तिरंगा यात्रा में विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में लोरमी क्षेत्र के कई गांवों में मोटर साइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली। गांवों की सड़कों और चौक-चौराहों से गुजरती यात्रा में देशभक्ति का गजब का उत्साह दिखाई दिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से गांव गूंज उठे। उप मुख्यमंत्री साव ने लोरमी के पुराना बस स्टैंड तहसील चौक झंझपुरी से अनेक गांव होते हुए दाऊकापा तक तिरंगा यात्रा निकाली, जो ग्राम डोंगरिया, उईकछार, अखरार, सारिसताल, धनियाडोली, अमलडीही, गोडखाम्ही और बोड़तराकला होते हुए आगे बढ़ी। गांवों की गलियों और ग्रामीण रास्तों पर लहराते तिरंगे ने देशभक्ति का संदेश दिया। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत किया।

यात्रा हरदी, खेकतरा और खैरवार होते हुए दाऊकापा पहुंची। जगह-जगह तिरंगे के प्रति सम्मान और देशप्रेम का भाव दिखाई दिया। तिरंगे की शान में बढ़ता हर कदम देश की एकता और अखंडता का संदेश दे रहा था। दाऊकापा में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान देश की आजादी के लिए



अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी का संकल्प लिया। उप मुख्यमंत्री श्री साव के नेतृत्व में लोरमी में भी मातृभूमि के प्रेम से सराबोर तिरंगा यात्रा निकली। मानस मंच से शुरू हुई यात्रा नगर के मुंगेली चौक, हटरी चौक, नया बस स्टैंड, गुरुद्वारा चौक, पुराना बस स्टैंड से होकर गुजरी। इस दौरान भारत

माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठा। नगरवासियों ने उत्साह के साथ यात्रा में सहभागिता की। हर ओर तिरंगे के प्रति सम्मान और देश के प्रति गर्व का भाव दिखाई दिया।

श्री साव ने कहा कि तिरंगा यात्रा वीर शहीदों को नमन करने और उनके बलिदान को याद करने का अवसर है। यह भारत माता के सम्मान और घर-घर देशभक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प है। वीर शहीदों के सपनों

तिरंगा हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक : वर्मा

■ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में दें योगदान

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रायपुर जिले के तिल्दा में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की महिमा और देश के गौरवशाली इतिहास का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हमारे तिरंगे का हरा रंग देश की शांति, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि इसके मध्य में स्थित अशोक चक्र हमें बिना रुके निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। यह ध्वज हमारी एकता और अखंडता का वह अनुपम प्रतीक है, जिसके मान-सम्मान की रक्षा के लिए देश के लाखों वीर सपूतों ने हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने उपस्थित जनसमूह और प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक 15 अगस्त के



पावन अवसर पर अपने-अपने घरों में पूरे स्वाभिमान के साथ तिरंगा जरूर फहराएं। इसके साथ ही उन्होंने ध्वज की गरिमा बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए कहारूण्डत्सव के बाद राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। सड़क, गली या किसी भी अनुचित स्थान पर तिरंगा गिरा हुआ न दिखाई दे, इस बात का ध्यान रखना हम सभी का परम नैतिक कर्तव्य है।

देश के स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा रखते हुए श्री वर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने और वर्ष 2047 तक एक सशक्त, समर्थ व विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का जो दूरदर्शी विजन रखा गया है, उसे हम सब मिलकर

साकार करेंगे।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला वर्मा, उपाध्यक्ष श्री पलक सुखमणि, पूर्व अध्यक्ष श्री महेश अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, युवा और विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे। देशभक्ति के नारों और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

रायपुर रेल मंडल में तिरंगा रैली सहित विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन



रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गय । इसी क्रम में रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों की सहभागिता से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। रैली के माध्यम से नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने तथा स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित

किया गया।हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रायपुर रेल मंडल में विभिन्न रचनात्मक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इनमें चित्रकला एवं पेंटिंग, रंगोली, कले मॉडलिंग तथा देशभक्ति गीत एवं कविता प्रतियोगिताएं प्रमुख किया गया। रैली में प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। रैली के माध्यम से नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने तथा स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित

माध्यम से बचत की आदत विकसित करने और बचाई गई राशि के उचित निवेश के विचार को सरल एवं व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा । राज्यपाल ने कहा कि बच्चों में पढ़ने, लिखने और नए विषयों पर विचार करने की आदत विकसित करना उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने दिव्यांश को अपनी जिज्ञासा, रचनात्मकता और सीखने की ललक को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर दिव्यांश के पिता श्री सुधीर सुलतानिया, माता श्रीमती सरिता सुलतानिया सहित अन्य परिजन उपस्थित थे।

को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक को योगदान देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें भी कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है। एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा।

तिरंगा यात्रा में लोरमी नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुजीत वर्मा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह, जिला पंचायत सदस्य सुश्री रत्ना काटले, श्रीमती अनिता साहू, श्री धनीराम यादव और श्री ज्योतिनंदन दुबे सहित पार्षदगण, एल्डरमैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए।

कलेक्टर, विधायक सहित हाथों में तिरंगा थाम दौड़े स्कूली बच्चे

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को रायपुर में जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्वाधीनता दिवस की प्रदेशवासियों को दी बधाई व शुभकामनाएँ

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों और राष्ट्र-निर्माताओं के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक नमन करने का दिन है। देश के 80वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए श्री देव ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' और 'तिरंगा यात्रा' से प्रदेश के कोने-कोने में राष्ट्रभक्ति का स्वर गुंजायमान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'तिरंगा यात्रा' एवं 'हर घर तिरंगा अभियान' ने जन-जन को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोया है। राज्य के युवाओं, माताओं,



बहनों और वरिष्ठ नागरिकों ने हाथों में तिरंगा थामकर देश के गौरव और स्वाभिमान को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है।

देव ने अपने संदेश में राज्य की प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार %सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास% के ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ रही है। कृषक उत्ति योजना, बकाया धान बोनस का भुगतान और महतारी वन्दन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्बल दिया है। राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन स्थापित किया गया है।

भारत विभाजन विभीषिका की घटनाओं का किया गया स्मरण



रायपुर। महंत लक्ष्मीनारायण महाविद्यालय, रायपुर के राष्टीय सेवा योजना इकाई द्वारा भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के सेमिनार कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत विभाजन के दौरान विस्थापन, संघर्ष और जनहानि की पीड़ादायक घटनाओं को स्मरण करना तथा भावी पीढ़ी को राष्टीय एकता, सद्भाव और सामाजिक समरसता के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. देवाशीष मुखर्जी, डॉ. आर. पी. दुबे, डॉ. राकेश चंद्राकर, डॉ. प्रेम चंद्राकर, डॉ. किरण अग्रवाल, डॉ. अर्चना मोडक तथा राष्टीय सेवा योजना के कार्यक्रम प्रभारी डॉ. लक्ष्मीकांत साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। वक्ताओं ने भारत विभाजन की ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं उसके मानवीय प्रभावों पर विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डॉ. देवाशीष मुखर्जी सहित डॉ. आर. पी. दुबे, डॉ. राकेश चंद्राकर, डॉ. लक्ष्मीकांत साहू तथा राष्टीय सेवा योजना की

दलनायिका वोणा यादव, लेपाक्षी वर्मा, प्रांजल वर्मा एवं प्रसांत साहू ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ स्वयंसेविका सिमरन सिंह ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दलनायक महेंद्र पटेल, गुलशन वर्मा, महक तिवारी, दुर्गेश साहू, प्रिंस झा, हिमांशु वर्मा , भवानी बेलोपानी , दीपक,शिल्पी एवं आकांक्षा नायक का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का समापन राष्टीय एकता, शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के संकल्प के साथ हुआ।

<

Credible Chhattisgarh विश्‍वसनीय छत्तीसगढ़	CGWB
कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़ जिला- रायगढ़ (छ.ग.) (ई-मेल: ee wrdmj@cgwrd.in) // निविदा निरस्तीकरण आदेश //	
पत्र क्रमांक 1490/ व.ले.लि./2026-27/धरमजयगढ़, दिनांक 13/08/2026 मुख्य अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के ज्ञाप क्र . सा-1-14 का-2026/1327, बिलासपुर 11.08.2026 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना का. 01/व.ले.लि./2026-27 दिनांक 29.05.2026 सिस्टम नं. 191813 (प्रथम आमंत्रण) "ख्महारपाकुट मध्यम जलाशय योजना के कुंजारा माईनर नहर का शीर्ष एवं मुख्य नहर जीर्णोद्धार, रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य निर्माण कार्य" (लागत राशि रू. 241.61 लाख) की निविदा को प्रथम आमंत्रण में निविदाकार की संख्या निरंक होने के कारण उक्त निविदा को "निरस्त" किया जाता है। (Old G. NO. 262701095)	
जी-262702770/9	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़,

भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं

सौरभ जैन अंकित

भारत का स्वतंत्रता संग्राम सही मायने में भारतीय समाज के आत्मसम्मान, अधिकारों और स्वशासन की आकांक्षाओं का व्यापक संघर्ष था। लगभग दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों, वर्गों और विचारधाराओं के लोगों ने संघर्ष किया। इस लंबे आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे जन-आंदोलन का स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों को अपनी राजनीतिक मांगों को संगठित रूप से उठाने का मंच मिला। प्रारंभिक दौर में दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विरोध किया। दादाभाई नौरोजी ने ‘धन निकासी सिद्धांत’ के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि औपनिवेशिक शासन भारत की संपदा को किस प्रकार बाहर ले जा रहा है। बीसवीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व्यापक जनभागीदारी वाली शक्ति बनी। गांधी ने सत्य और अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बनाया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन ने किसानों और श्रमिकों के बीच उनकी लड़ाई लड़कर कांग्रेस नेतृत्व को स्थापित किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नौंव को चुनौती दी। महात्मा गांधी का तब सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने स्वतंत्रता के प्रश्न को आम भारतीयों के जीवन और अधिकारों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन को आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टि देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक बने। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नेहरू ने जेल यात्राओं और आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। स्वतंत्र भारत के लिए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच की मजबूत आधारभूमि तैयार की। स्वतंत्रता संग्राम में केवल कांग्रेस और उसके प्रमुख नेताओं का ही योगदान नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। सरदार पटेल ने किसान आंदोलनों और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन को समाज के हर वर्ग से जोड़ दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने राष्ट्रीय एकता और हिंदू-मुस्लिम एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी आंदोलनरत महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। बड़ी संख्या में महिलाओं को भी इस जन आंदोलन से जोड़ा। भारत की आजादी किसी एक नेता, संगठन या आंदोलन का परिणाम नहीं थी। यह वर्षों तक चले राजनीतिक संघर्ष, जनआंदोलनों, क्रांतिकारी गतिविधियों, सामाजिक जागरण और असंख्य ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के त्याग का परिणाम 15 अगस्त 1947 की आजादी थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मंच दिया, गांधी ने आंदोलन को जनशक्ति और नैतिक आधार प्रदान किया, नेहरू ने आधुनिक भारत की कल्पना को दिशा दी, लाखों सेनानियों ने अपने संघर्ष और जान माल के बलिदान से स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। इसी सामूहिक प्रयास ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यथा-
पुरा मैथुनमाश्रित्य स्थिताभ्यां तु हिमालये ।
भीमोमाभ्यां महाबाहो । रक्तविन्दुश्चयुतः क्षितौ ॥
मेदिन्या सप्रत्ययेन सुखेन विधृतोऽनया ।
जातोऽस्याः स कुजो वीरो रको रक्तसमुद्भवः ॥
(भविष्य-पुराण ब्राह्म पर्व 31 । 17-18)
अर्थात्- हिमालय (जलीय सृष्टि हो जाने के बाद) में स्थित हुवे शिव पार्वती (= पुरुष और प्रकृति) संघर्ष से एक रक्तविन्दु (= आग्नेय वाष्प का गाढ़ा पिण्ड) पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी ने उसे धारण किया। समय आने पर वही पृथ्वी का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे कुज कहते हैं।

उपर्युक्त वर्णन से पता चलता है कि वर्तमान भीम किसी समय हमारी पृथ्वी से संयुक्त था और समयान्तर में वह आकर्षण विकर्षण के वैषम्य से जुदा हो गया। साथ ही इस जुदाई में हमारी पृथ्वी का बहुत

कुछ भाग अपने साथ ले गया। सम्भव है आज जापान और अमेरिका के मध्य में जो शान्त महासागर दीख पड़ता है वह उसी खाली स्थान का स्मारक हो। कई आधुनिक भूगर्भ विद्या-विशारदों का ऐसा अनुमान भी है, परन्तु यह इदमित्थं कौन कह सकता है। अस्तु, कुछ भी हो आधुनिक खोज ने पौराणिक भीम नाम का समर्थन अवश्य किया है। यही बताना हमारा लक्ष्य है। इसीप्रकार शनि का सूर्यपुत्र होना और बुध का चन्द्रपुत्र होना भी एक खगौलिक पुरातन घटना का परिचायक है, जिसे हम स्थानाभाव से यहां लिख नहीं सकते। जिन सज्जनों को खगोल विद्या से प्रेम हो उन्हें कूर्मपुराण, भविष्यपुराण या श्रीमद्भागवत पुराण (स्कन्ध 5 ओ 16 से 26) का श्रद्धापूर्वक पारायण करना चाहिये फिर मालूम होगा कि वर्तमान खगोलवेत्ताओं ने पौराणिक खगोल की किस प्रकार पुनरावृत्ति की है।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

तिरंगा : भारत की आन, बान और शान

हर्षवर्धन पान्डे

किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज उसके स्वतंत्र होने का संकेत है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल एक कपड़े या कागज़ का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह भारत की आत्मा, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। इसके तीन रंग केसरिया, सफेद, हरा और मध्य में अशोक चक्र भारतीयता के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। तिरंगा न केवल स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को बतलाता है, बल्कि यह भारत की एकता, विविधता और आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। तिरंगे ने अपने रंगों से दुनिया में अपनी अद्वितीय छवि बनाई है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए हथकरघा खादी (सूती या रेशमी) कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे झंडे में नीले रंग का अशोक चक्र धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है।

तिरंगे का केसरिया रंग साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारतीयता का यह पहलू हमें स्वःस्वार्थ भाव से देश के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है। इसी तरह से सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक यह रंग भारत की अहिंसावादी विचारधारा को रेखांकित करता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि विश्व को शांति का संदेश भी दिया। यह रंग भारतीयता की उस भावना को दर्शाता है जो सहिष्णुता और सामंजस्य में विश्वास रखती है। हरा रंग समृद्धि, उर्वरता और प्रकृति के प्रति भारत की गहरी आस्था को दर्शाता है। भारत की संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण का विशेष स्थान रहा है। यह रंग हमें सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है। यह सम्राट अशोक के धर्म चक्र से प्रेरित है जो न्याय, धर्म और नैतिकता का दर्शाता है। यह चक्र भारतीयता के उस दर्शन को दर्शाता है जो निरंतर प्रगति और नैतिकता के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। भारतीयता एक ऐसी अवधारणा है जो भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विविधता को समेटे हुए है। तिरंगा इस भारतीयता का एक जीवंत प्रतीक है।

भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों



और परंपराओं का देश है। तिरंगा इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। जैसे तिरंगे के तीन रंग एक साथ मिलकर एक पूर्ण ध्वज बनाते हैं वैसे ही भारत की विभिन्न संस्कृतियाँ और समुदाय एक साथ मिलकर भारतीयता का निर्माण करते हैं। यह ध्वज हमें सिखाता है कि भिन्नताओं के बावजूद हम एक हैं। तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रहा है। यह उन असंख्य बलिदानों का प्रतीक है जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाई। भारतीयता का यह पहलू हमें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ता है। तिरंगा हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता अनमोल है और इसे बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयास करना होगा।

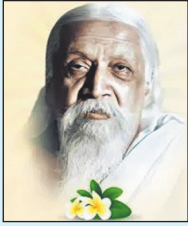
भारतीय इतिहास में 1905 से पहले पूरे भारत की अखंडता को दर्शाने के लिए कोई राष्ट्र ध्वज नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1905 में स्वामी विवेकानंद की शिष्य सिस्टर निवेदिता ने पहली बार पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की थी। सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाए गए ध्वज में कुल 108 ज्योतियाँ बनाई गई थी। यह ध्वज चौकोर आकार का था। ध्वज के दो रंग थे- लाल और पीला। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम और पीला रंग विजय का प्रतीक था। ध्वज पर बंगाली भाषा में वंदे-मातरम् लिखा गया था और इसके पास वज्र (एक प्रकार का हथियार) और केन्द्र में एक सफेद कमल का चित्र भी था। वर्तमान में इस ध्वज को आचार्य बाल गंगाधर तिलक, कोलकाता में संरक्षित रखा गया है। इसके बाद 7 अगस्त 1906 को कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के पारसी बागान चौक में ध्वज को फहराया गया। कोलकाता ध्वज प्रथम भारतीय अनाधिकारिक ध्वज था। इसकी अभिकल्पना शचिन्द्र प्रसाद बोस ने की थी। झंडे में बराबर चौड़ाई की तीन क्षैतिज पट्टियाँ थीं। शीर्ष धारी नारंगी, केंद्र धारी पीली और निचली पट्टी हरे रंग की थी। शीर्ष पट्टी पर ब्रिटिश-

शासित भारत के आठ प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 आधे खुले कमल के फूल थे और निचली पट्टी पर बाईं तरफ सूर्य और दाईं तरफ एक वर्धमान चौद की तस्वीर अंकित थी। ध्वज के केंद्र में वन्दे-मातरम् का नारा अंकित किया गया था। इसी तरह पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस केस्टुटार्ट में फहराया गया था। इस ध्वज को सप्तर्षि झंडे' के नाम से जाना जाता है। यह ध्वज काफी कुछ वर्ष 1906 के झंडे जैसा ही था लेकिन इसमें सबसे ऊपरी पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाए सात तारे सप्तर्षि के प्रतीक थे।

भारतीय धरती पर तीसरे प्रकार का तिरंगा होम रूल लीग के दौरान फहराया गया था। होम रूल आंदोलन के दौरान कोलकाता में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह ध्वज फहराया गया था। उस समय ध्वज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें 9 पट्टियाँ थीं, जिसमें 5 लाल रंग और 4 हरे रंग की थी। ध्वज के ऊपरी बाएं कोने में यूनियन जैक था। शीर्ष दाएँ कोने में अर्धचंद्र और सितारा था। ध्वज के बाकी हिस्सों में सप्तर्षि के स्वरूप में सात सितारों को व्यवस्थित किया गया था। वर्ष 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगले वेंकय्या ने बिजावाड़ा (अब विजयवाड़ा) में गांधीजी के निर्देशों के अनुसार सफेद,हरे और लाल रंग में पहला चरखा-झंडा डिजाइन किया था। इस ध्वज को स्वराज-झंडे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। इस वर्ष तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा के बाद भारतीय नेताओं को स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता का एहसास हुआ। तदनुसार ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए एक तदर्थ ध्वज समिति का गठन किया गया। सूरैया बद्र-उद-दीन तैयब द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 17 जुलाई 1947 को ध्वज समिति द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया गया था। समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तिरंगे में तीन समान चौड़ाई की

महर्षि अरविन्द



कांग्रेस के गरमपंथी धड़े की विचारधारा को बढ़ावा दिया। सन् 1906 में जब बंग-भंग का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बड़ौदा से कलकत्ता की ओर प्रस्थान कर दिया। जनता को जागृत करने के लिए अरविन्द ने उत्तेजक भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषणों तथा %बंदे मातरम्% में प्रकाशित लेखों द्वारा अंग्रेज सरकार की दमन नीति की कड़ी निंदा की थी।

अरविन्द का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा और 1908-09 में उन पर अलीपुर बमकांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल की सजा सुना दी।

अरविन्द ने कहा था चाहे सरकार

क्रांतिकारियों को जेल में बंद करे, फांसी दे या यातनाएं दे, पर हम यह सब सहन करेंगे और यह स्वतंत्रता का आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। एक दिन अवश्य आएगा, जब अंग्रेजों को हिन्दुस्तान छोड़कर जाना होगा।

यह इतेफाक नहीं है कि 15

अगस्त को भारत को आजादी मिली और इसी दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है।

जब सजा के लिए उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया तो जेल में अरविन्द का जीवन ही बदल गया। वे जेल की कोठरी में ज्यदा से ज्यदा समय साधना और तप में लगाने लगे। वे गीता पढ़ा करते और भगवान श्रीकृष्ण की आराधना किया करते। ऐसा कहा जाता है कि अरविन्द जब अलीपुर जेल में थे, तब उन्हें साधना के दौरान भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण की

क्षैतिज पट्टियाँ हैं जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के विकास और उर्वरता को दर्शाती है। तिरंगे के केंद्र में सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र एक दिन के 24 घंटों और हमारे देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। तिरंगे को भारत की महिलाओं की ओर से 14 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के अर्द्ध-रात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था।

भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी, 1950 को अपनाया था। भारत के तिरंगे झंडे के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। भारत का राज चिन्ह अशोक स्तम्भ के शीर्ष की एक प्रतिकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। अशोक स्तम्भ तीन शेरों की आकृति जिसके नीचे एक चौखट के बीच में एक धर्म चक्र है। इस चक्र के दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर एक अश्व है। चौखट के आधार पर 'सत्यमेव जयते' शब्द अंकित है। भारत के राजचिन्ह में तीन प्रकार के छ- जानवर हैं-शेर (चार), बैल (एक), अश्व (एक) भारत का यह चिन्ह भारत की एकता का चोतक है। राष्ट्रीय चिन्ह के दो भाग शीर्ष और आधार हैं। शीर्ष पर शेर साहस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दायीं ओर एक बैल है तथा बायीं ओर एक घोड़ा है जो स्मूर्ति का ताकत व गति का। ‘सत्यमेव जयते’ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ‘सत्यमेव जयते’ का अर्थ सत्य की ही विजय है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र 1947 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 2002 से पल्लेग कोड बदल गया है। भारतीयों को कहीं भी किसी भी समय गर्व के साथ झंडा फहराने की आजादी दे दी गयी है। अभी कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 ए अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था जिसके बाद देश में भारतीय ध्वज को दिन –रात फहराने की अनुमति दे दी गई है।

15 अगस्त 1947 आजाद भारत के इतिहास का ऐतिहासिक दिन था जब अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाकर भारत में नई सुबह हुई थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार देशवासियों ने खुली हवा में सौँस ली और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ।

आज का इतिहास

1772 ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिलों में अलग दौदाबी और फौजदारी अदालतों के गठन का निर्णय लिया।

1854 ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली के बीच 37 किलोमीटर की दूरी में पहली यात्री ट्रेन चलायी। हालाँकि इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 1885 में किया गया।

1947 युगवाणी (पत्रिका) – देहरादून (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका। यह आरंभ एक पक्षिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था जो कालान्तर में पहाड़ का प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र बना।

1950 भारत में 8.6 के तीव्रता वाले भूकम्प के कारण 20 से 30 हजार लोग मारे गये।

1971 बहरीन ब्रिटेन के शासन से आजाद हुआ।
1972 पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्थात् पिन कोड लागू किया गया।
1979 फरीदाबाद – हरियाणा का 12 वॉ ज़िला बना।
1982 राष्ट्रवाणी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का दिल्ली में उद्घाटन किया गया।

1990 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

1907 इंडियन बैंक – स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई।

1994 सूडान के चार्टरूम में आतंकवादी कार्लोस पकड़ा गया।
1998 उत्तरी आयरलैंड में ओमाग द्वारा की गई बमबारी में 29 लोग मारे गये और 220 अन्य घायल हुए।

1947 स्वतंत्रता दिवस – भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

1975 बांग्लादेश में सैनिक क्रान्ति, मुजीबुर्रहमान की हत्या तथा खोंडेकर मुश्ताक अहमद के नेतृत्व में नयी सरकार का गठन।

1989 स्लोव्ने में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की।

2000 उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बिछड़े नागरिक आपस में मिले।

2002 संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्लामाबाद स्थित अपने सूचना केन्द्र की बन्द किया।

2004 लारा सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।

2007 दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के मध्य तटीय इलाके में 8.0 तीव्रता के भूकंप से 500 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोग बेघर हुए।

2008 स्वतन्त्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद भवन परिसर में स्वतन्त्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।

आजादी का जश्न मना रहे बलूचों पर पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक

नीरज कुमार दुबे

अपनी आजादी का जश्न मना रहे बलूचिस्तानियों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। इसके जवाब में बलुच लड़ाकों ने बंदूकें उठा लीं और पाकिस्तानी सेना पर कई जगह ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते सोराब और ग्वादर से लेकर चागाई, खुजदार, वाध, मंगुचर और झाओ तक हिंसा फैल गई और दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया। पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 21 नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि जवाबी हमलों में बलुच विद्रोहियों ने पुलिस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस तरह बलूचिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान की सैन्य ताकत और बलूचों की आजादी की लड़ाई के बीच सीधे टकराव का मैदान बन गया है।

स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी विमानों ने अलग-थलग आतंकी ठिकानों की बजाय आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया। हमलों के बाद सोराब और ग्वादर में विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने सैन्य कार्रवाई के खिलाफ

आवाज उठाते हुए जवाबदेही की मांग की। हम आपको बता दें कि बलूचों को जबरन गायब कर देना, सुरक्षा अभियानों के नाम पर बलूचों से बदसलूकी, बलुच महिलाओं के शोषण, उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति पर पारबंदियों और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों ने पाकिस्तान के खिलाफ स्थानीय असंतोष को दशकों से लगातार गहरा किया है।

देखा जाये तो बलूचिस्तान का संकट अचानक पैदा हुआ कोई सुरक्षा संकट नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, खनिज, ऊर्जा और रणनीतिक समुद्री क्षेत्र से बेहद समृद्ध है, लेकिन स्थानीय आबादी लंबे समय से खुद को विकास और संसाधनों के लाभ से वंचित मानती रही है। बलूच राष्ट्रवादियों का आरोप है कि इस प्राकृतिक संपदा का फायदा स्थानीय लोगों की बजाय पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान को मिलता है। साथ ही वह पंजाबी प्रभुत्व वाले संघीय ढांचे पर राजनीतिक और जातीय भेदभाव का आरोप लगाते हैं।

इसी असंतोष ने आत्मनिर्णय की उस लंबी लड़ाई को जन्म दिया, जिसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में



बदल दिया है। साथ ही बलूच राष्ट्रवादियों का कहना है कि 1947 में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने के समय कलात खानत ने अपनी संप्रभुता का दावा किया था। 11 अगस्त इसी ऐतिहासिक घटना की याद में बलूच राष्ट्रवादियों के लिए प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस है। उनका दावा है कि मार्च 1948 में पाकिस्तान में विलय का फैसला स्वतंत्र इच्छा से नहीं, बल्कि दबाव में कराया गया। हालाँकि पाकिस्तान इस दावे को स्वीकार नहीं करता और 14 अगस्त को ही बलूचिस्तान समेत पूरे देश का स्वतंत्रता दिवस मानता है। दूसरी ओर, इस बार 11 अगस्त का

संदेश केवल प्रतीकात्मक नहीं रहा। बलूच राष्ट्रवादियों ने इसे अपनी राजनीतिक पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा के रूप में पेश किया। सोशल मीडिया पर कुछ बलुच समर्थकों ने दावा किया कि भविष्य में अलग ‘रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान’ के लिए पासपोर्ट, मुद्रा और

दूतावास जैसी संस्थाओं की तैयारी की जा रही है। उधर, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद हालात और विस्फोटक हो गए। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने इसके समानांतर कई जिलों में समन्वित हमले किए। चागाई में आधी रात को पुलिस स्टेशन पर बम हमला कर उसे नष्ट किए जाने और तीन सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। यक्माच में वाणिज्यिक वाहनों पर घात लगाकर हमला और एक ट्रक हाईजैक किए जाने की सूचना सामने आई। खुजदार आरसीडी हाईवे पर

सुरक्षा काफिले और बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाए जाने, वाध में सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला करने, मंगुचर बाजार में सुरक्षा चौकी पर विस्फोट और भारी गोलीबारी तथा झाओ में पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर रात में हमले की रिपोर्ट है।

साथ ही बीएलए ने इस महीने अलग-अलग हमलों में कम से कम 32 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा भी किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में मुठभेड़ों के दौरान 10 उग्रवादियों को मार गिराया। एक कार बम के समय से पहले फटने की घटना में आठ आतंकि्यों और पास के घर में मौजूद तीन लोगों समेत 11 लोगों के मारे जाने की बात भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने कही है।

देखा जाये तो इन घटनाओं को अलग-अलग हमलों के रूप में देखना बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करना होगा। बलूचिस्तान में अब एक खतरनाक चक्र बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई, नागरिकों में आक्रोश, बलूच विद्रोहियों की जवाबी हिंसा और फिर और कठोर सैन्य अभियान। यही चक्र इस संघर्ष को लगातार गहरा कर रहा है।

बलूचिस्तानियों की आजादी की लड़ाई की ‘सफलता’ को फिलहाल पाकिस्तान से वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि दशकों के दमन, सैन्य अभियानों और राजनीतिक असंतोष के बावजूद स्वतंत्रता की मांग खत्म नहीं हुई। बल्कि 11 अगस्त जैसे प्रतीक, सड़कों पर विरोध और बीएलए जैसे सशस्त्र संगठनों की बढ़ती गतिविधियां बताते हैं कि बलूच सवाल अब भी पाकिस्तान के सामने एक गंभीर और जटिल चुनौती है।

बहरहाल, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह बलूचिस्तान को केवल बंदूक और एयर स्ट्राइक से नियंत्रित कर पाएगा। क्योंकि जिस संघर्ष को दशकों तक सुरक्षा समस्या बताकर दबाने की कोशिश की गई, वह अब राजनीतिक पहचान, संसाधनों पर अधिकार और आत्मनिर्णय की मांग से जुड़ा व्यापक संकट बन चुका है। और जब किसी जमीन पर लोग अपनी आजादी का दिन मनाने के लिए भी डर और गोलियों के साये में खड़े हों, तो यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं रहता, यह उस राज्य की वैधता पर उठता एक बेहद गंभीर सवाल बन जाता है।

मध्यप्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर की सक्रियता के मायने क्या?

सुरेश तिवारी

मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। दो दिवसीय दिल्ली यात्रा के दौरान तोमर ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट की। इसी दौरान दिल्ली में कई नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की, जिनमें मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा भी शामिल हैं।

देखा जाए तो दत्तिया उपचुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां दिल्ली में तेज हो गई हैं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद वीडी शर्मा की प्रधानमंत्री और अमित शाह से भेंट हुई, वहीं कैलाश विजयवर्गीय की अमित शाह के साथ लंबी चर्चा हुई। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय और प्रह्लाद पटेल की मुलाकात ने भी राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को हवा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है?

मध्य प्रदेश की नौकरशाही में इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1993 बैच के तीन अधिकारियों की तिकड़ी काफी चर्चा में है। ये तीनों अधिकारी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंसलोई, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण राजन शामिल हैं। नौकरशाही में चर्चा है कि मुख्यमंत्री इन तीनों अधिकारियों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वहीं, मध्य प्रदेश कैंडर के 1993 बैच की एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी भी इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही

में उन्हें केंद्र सरकार में उच्च शिक्षा सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिली है, जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश और दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों में हो रही है।

मध्य प्रदेश कैंडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी वी.एल. कांता राव को केंद्र सरकार में हाल ही में हुए फेरबदल के दौरान गृह मंत्रालय के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले राजभाषा विभाग का सचिव बनाया गया है। डीओपीटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार फिलहाल उन्हें ओएसडी नियुक्त किया गया है। वे 30 सितंबर को अंशुली आर्य के सेवानिवृत्त होने के बाद सचिव का कार्यभार संभालेंगे।

यानी अगले लगभग डेढ़ महीने तक उनके पास कोई विशेष प्रशासनिक दायित्व नहीं रहेगा। गौरतलब है कि कांता राव पहले इस्पात मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग के सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में वे जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग जैसे सरका की प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण विभाग में कार्यरत थे। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश कैंडर की दो महिला आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी और पल्लवी जैन गोविल को केंद्र में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दोनों 1993 बैच की अधिकारी हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम जल्द गठित होने जा रही है। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। मध्य प्रदेश से जिन नेताओं के नाम इस टीम के लिए चर्चा में हैं, उनमें एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। उसके अलावा एक महिला नेता और अनुसूचित जाति वर्ग के एक वरिष्ठ नेता का नाम भी संभावित दवेदारों में शामिल है। मध्य प्रदेश भाजपा की मीडिया टीम से जुड़े एक प्रमुख चेहरे की भी नई टीम में जगह मिलने की चर्चा है।

विदेशी चंदे पर नियंत्रण और संतुलन की अपेक्षा

ललित गर्ग

12 अगस्त 2026 का दिन भारतीय संसद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एफसीआरए विधेयक को लोकसभा ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति- जेपीसी के पास भेज दिया। यह फैसला केवल एक विधेयक को संसदीय प्रक्रिया के अगले चरण में भेजना नहीं है, बल्कि उस व्यापक बहस का अवसर है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी धन की पारदर्शिता, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्वायत्तता, नागरिक समाज की भूमिका और लोकतांत्रिक अधिकार-सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। विधेयक को जेपीसी के पास भेजे जाने से सरकार और विपक्ष के बीच तत्काल टकराव को कुछ हद तक विमर्श में बदलने का अवसर मिला है। एफसीआरए का इतिहास भी इस बहस की गंभीरता को समझने में मदद करता है। विदेशी धन के माध्यम से देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बाहरी प्रभाव की आशंकाओं को देखते हुए 1976 में पहली बार कानून बनाया गया था। वर्ष 2010 में इसे नए एफसीआरए कानून से प्रतिस्थापित किया गया और उसके बाद 2020 सहित विभिन्न चरणों में इसके प्रावधान अधिक करतार होते गए। आज यह कानून केवल विदेशी चंदे की प्राप्ति और उसके उपयोग का लेखा-जोखा रखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े विमर्श का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

आंकड़े इस विषय की व्यापकता बताते हैं। पीआरएस के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक 14,449 एफसीआरए प्रमाणपत्र सक्रिय थे, जबकि 22,498 रद्द और 15,212 समाप्त माने गए। 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को लगभग 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान मिला। इन आंकड़ों को देखकर यह सवाल स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग कहां, किस उद्देश्य से और किस स्तर की निगरानी के साथ हुआ? लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी उत्पना ही महत्वपूर्ण है-क्या किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाना अपने आप में किसी वित्तीय या आपराधिक अनियमितता का प्रमाण माना जा सकता है? सरकार के अपने स्पष्टीकरण के अनुसार भी पंजीकरण समाप्त होने के कई कारण हो सकते हैं और हर समाप्ति को गलत काम से जोड़ना उचित नहीं



हैं। यहीं से प्रस्तावित संशोधन का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। विधेयक में ‘नामित प्राधिकरण’ की व्यवस्था प्रस्तावित है। यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है, वह स्वयं पंजीकरण छोड़ देती है या उसका प्रमाणपत्र नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियां पहले अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण के अधीन आ सकती हैं। यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल नहीं होता तो संपत्तियां स्थायी रूप से निहित की जा सकती हैं तथा उन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग या बेचने का प्रावधान है। बिना इसी प्राप्ति और अप्रयुक्त विदेशी अंशदान भारत की समेकित निधि में जमा किए जाने का प्रस्ताव है।

भारत में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विदेशी वित्तपोषण के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं अथवा राष्ट्रीय हित से टकराने वाली गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं। इसलिए एफसीआरए का मूल उद्देश्य-विदेशी अंशदान को पारदर्शी, उत्तरदायी और वैध उद्देश्यों तक सीमित रखना-न तो अनुचित है और न ही लोकतंत्र विरोधी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और प्रशासनिक शक्ति के विस्तार के बीच एक स्पष्ट रेखा भी होनी चाहिए। यही इस विधेयक की असली परीक्षा है। यदि किसी संस्था ने विदेशी धन का इस्तेमाल आतंकवाद, हिंसा, अलगाववाद, जबरन या प्रलोभन आधारित धर्मोत्तरण, राजनीतिक अस्थिरता अथवा भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किया है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। राहित में ऐसी कठोरता आवश्यक है। मगर दूसरी ओर यह कोई संस्था अस्पताल चला रही है, गरीबों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा रही है, पर्यावरण संरक्षण कर रही है, महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही है अथवा प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचा रही है, तो केवल तकनीकी या प्रक्रियागत चूक के कारण उसके वर्षों के सामाजिक

कार्य और विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर तत्काल सरकारी नियंत्रण स्थापित हो जाना चिंता का विषय बन सकता है। यही कारण है कि जेपीसी के पास जाना इस विधेयक के लिए एक सकारात्मक अवसर है। संसद में बहुमत से कानून पारित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जिन कानूनों का प्रभाव हजारों संस्थाओं, लाखों लाभांशियों और देश के व्यापक नागरिक समाज पर पड़ता हो, उनकी बारीकी से जांच लोकतंत्र को मजबूत करती है। जेपीसी में विपक्ष अपनी आपत्तियां रख सकता है, सरकार अपने तर्क स्पष्ट कर सकती है और विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, वित्तीय विशेषज्ञों तथा सुरक्षा एजेंसियों के अनुभवों को भी सामने लाया जा सकता है।

विधेयक में एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी प्रावधान यह भी है कि धार्मिक स्थल की धार्मिक प्रकृति को बनाए रखना अनिवार्य होगा। नामित प्राधिकरण किसी ऐसे स्थल को दूसरे उद्देश्य में बदल या उसकी धार्मिक प्रकृति समाप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रभावित संस्था को 90 दिनों के भीतर पुनरीक्षण का अधिकार और जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील का प्रावधान दिया गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि पंजीकरण बहाल होने पर अस्थायी रूप से निहित संपत्तियां और अप्रयुक्त धन वापस किए जाएंगे। ये प्रावधान स्वागत योग्य हैं, लेकिन सवाल यह रहेगा कि इन अधिकारों की वास्तविक स्वतंत्रता और प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन नवीनीकरण से जुड़ा है। 2026 के नियमों में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये विदेशी अंशदान के उपयोग को सक्रिय संस्था की पहचान के रूप में रखा गया है। साथ ही गतिविधि और राज्य-विशिष्ट पंजीकरण तथा अधिक विस्तृत उपयोग संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था निष्क्रिय संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जेपीसी को यह भी देखना होगा कि क्या हर छोटी लेकिन वास्तविक सामाजिक संस्था के लिए 10 लाख रुपये खर्च करना व्यावहारिक मानदंड है। सामाजिक उपयोगिता का मूल्य केवल धनराशि से नहीं किया जा सकता। एफसीआरए की बहस को केवल ‘सरकार बनाम विपक्ष’ या ‘राष्ट्रवाद बनाम नागरिक स्वतंत्रता’ के द्वंद में सीमित करना भी उचित नहीं होगा।



सवाल से जुड़े हुए थे। इस दौर में राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप लगातार बदल रहा था। यह बदलाव केवल रंगों या डिजाइन का बदलाव नहीं था, बल्कि भारत की राजनीतिक सोच के विकसित होने का भी संकेत था।

1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले होम रूल आंदोलन के दौरान एक और ध्वज सामने आया। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की मांग को अभिव्यक्त करना था। यानी ध्वज अब केवल राष्ट्रीय भावना का प्रतीक नहीं था, बल्कि राजनीतिक अधिकारों और स्वशासन की मांग का भी प्रतीक बनने लगा था। भारत की स्वतंत्रता की मांग जैसे-जैसे स्पष्ट होती गई, वैसे-वैसे एक ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक की आवश्यकता भी महसूस होने लगी जिसमें देश की विविधता और एकता दोनों दिखाई दें।

इसी पृष्ठभूमि में पिंगली वेंकैया का नाम सामने आता है। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन और विभिन्न देशों के झंडों के अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे। 1921 में विजयवाड़ा में उन्होंने महात्मा गांधी के सामने राष्ट्रीय ध्वज का एक डिजाइन प्रस्तुत किया। सरकारी श्रोतों के अनुसार उस समय के प्रारंभिक डिजाइन में लाल और हरे रंग की पट्टियां थीं और बाद में सफेद रंग तथा चरखे को शामिल किया गया। चरखा स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। पिंगली वेंकैया को इसलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति के रूप में یاد दिया जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आज का तिरंगा उनके 1921 के प्रारंभिक डिजाइन का हबहुब रूप नहीं है। अगले वर्षों में ध्वज के स्वरूप और उसके प्रतीकों में बदलाव होते रहे और अंततः स्वतंत्र भारत के लिए वर्तमान स्वरूप सामने आया।

राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा में 1931 एक बेहद महत्वपूर्ण

प्रभु चावला

सत्ता हमेशा उस शक्ति को लेकर संदेह करती रही है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। सरकारें अपनी वैधता चुनावों से प्राप्त करती हैं, लेकिन वे हमेशा उन संस्थाओं के साथ सहज नहीं रही हैं जो बिना जनता का वोट लिए समाज को प्रभावित करती हैं। नागरिक समाज की स्थापना राज्य को सुधारने के लिए हुई थी, उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं; उसका काम समझाना और प्रभावित करना था, दबाव डालना नहीं।

जब यह सीमा धुंधली होने लगती है, तो एक पोपकारती उद्देश्य भी एक अस्पष्ट और संदिग्ध राजनीतिक पहचान हासिल कर सकता है और अपने आपको सत्ता के एक समानांतर केंद्र में बदल सकता है। भारत अब एक निर्वाचित सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के विशाल समूह के बीच इसी असहज टकराव का सामना कर रहा है, जिसे कुछ लोग ‘तीसरा क्षेत्र’ कहते हैं।

तत्काल टकराव भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधनों को लेकर है। भाजपा और संघ परिवार लंबे समय से एनजीओ प्रतिष्ठान के कुछ हिस्सों को पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव को बनाए रखने और भारत के सभ्यतागत प्रतीकों को कमजोर करने वाले साधन के रूप में देखते रहे हैं।

हाल ही में भाजपा नेताओं ने यह आरोप भी लगाया कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों की युवा प्रदर्शनों में भूमिका रही है। इसलिए मौजूदा विधायी प्रयास को विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने और अधिक पारदर्शिता लागू करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्ष इसे भगवा प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाली संस्थाओं का गला घोटने की कोशिश मानता है।

विशेष रूप से इसाई संगठन इस बात से चिंतित हैं कि वैध स्कूल, अस्पताल और धर्मार्थ संस्थाएं भी लगातार कठोर होते नियामक ढांचे में फंस सकती हैं। भारत संभवतः दुनिया में सबसे बड़ा और निश्चित रूप से एनजीओ के लिए सबसे अनुकूल वातावरण वाला देश है। सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन

एनजीओ को कौन नियंत्रित, निर्देशित करता है?

में 2009 में इनकी संख्या 33 लाख आंकी गई थी – लगभग हर 400 भारतीयों पर एक संगठन। यह आंकड़ा पुराना है और अंतरराष्ट्रीय तुलना भी कठिन है, क्योंकि अलग-अलग देशों में एनजीओ को वार्गीकृत और पंजीकृत करने के तरीके अलग-अलग हैं।

पैसा क्षमता पैदा करता है, क्षमता प्रभाव पैदा करती है और प्रभाव अंततः शक्ति में बदल जाता है। लेकिन इन संगठनों का संचालन अलग-अलग संस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और वैचारिक ढांचों के माध्यम से होता है। इनके स्वामित्व, उद्देश्यों या कार्यप्रणाली में कोई एकरूपता नहीं है। यही कारण है कि पारदर्शिता की आवश्यकता कम नहीं, बल्कि और अधिक बढ़ जाती है।

सरकारें निर्वाचित होती हैं और मतदाताओं, संसद, न्यायपालिका तथा संविधान के प्रति जवाबदेह होती हैं। जबकि एनजीओ स्वयंस्थापित संस्थाएं हैं और उनकी वैधता जनता के विश्वास से आती है। वे सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, उसकी विफलताएं उजागर कर सकते हैं, उपेक्षित मुद्दों के लिए अभियान चला सकते हैं और सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में सरकार की सहायता कर सकते हैं।

वे सुधार कर सकते हैं, लेकिन दबाव डालकर शासन नहीं कर सकते। वे वकालत कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचित विपक्ष का जनादेश अपने हाथ में नहीं ले सकते। और यदि वे राज्य से पारदर्शिता की मांग करते हैं, तो वे अपने वित्त, संबद्धताओं और उद्देश्यों पर उड़ाए गए सवालों को उत्पीड़न नहीं मान सकते।

मोदी सरकार ऐसे क्षेत्र को ‘शुद्ध’ करने के लिए दृढ़ है, जिसने हमेशा जवाबदेही की समान संस्कृति प्रदर्शित किए बिना धन और प्रभाव अर्जित किया है। सरकार को वास्तविक वित्तीय और राजनीतिक गठजोड़ों को उजागर करना चाहिए, लेकिन वास्तविक धर्मार्थ संस्थाओं को पंगु नहीं बनाना चाहिए। दूसरी ओर, एनजीओ प्रतिष्ठानों को यह स्वीकार करना होगा कि नैतिक उद्देश्य किसी संस्था को जांच से छूट नहीं देता। एक स्वस्थ लोकतंत्र को जवाबदेही और संतुलन की आवश्यकता होती है, न कि जवाबदेही से मुक्त सत्ता के प्रतिस्पर्धी केंद्रों की।

सपा पर बरसे अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि पेपर लीक आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है। इसका शिकार युवा होता है। इस बीमारी का इलाज हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे। हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में मिली है। हर जख्म का इलाज मोदी सरकार ने ही किया है। आतंकवाद-नक्सलवाद को जड़

से खतम करने का काम भी हमने ही किया है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है और यह किया है कि ऐसा कानून लाएंगे, जो सख्त होगा। आज का यह कानून आप देखिए, 2024 के कानून में संशोधन करने के लिए लाए हैं। हम सिस्टम को और फुलफ्रूफ करना चाहते हैं। तारीख पर तारीख न हो, इसके लिए सिस्टम बनाने जा रहे हैं। आप तो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे, सदन चलने नहीं दे रहे थे, राहुल गांधी को लगा कि युवाओं ने पूछा नहीं, अखिलेश जी के साथ जाकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर लट गए, आपकी तड़प समझ रहा हूँ, अंदर जाने का मौका कभी नहीं मिलने वाला है। नीट एग्जाम में जैसे ही लीक जैसा कुछ होने की खबर आई, हमारी सरकार ने तीन दिन में फिर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया। 40 हजार से ज्यादा सेंटर पर कराया।

देव आनंद के बेटे का हार्ट अटैक से निधन

नई दिल्ली। बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार दिवंगत देव आनंद के परिवार से एक बुरी खबर सामने आई है, उनके बेटे सुनील आनंद अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने 70 की उम्र में अपनी अंतिम सांस लंदन में लीं. उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उनका निधन हुआ. ये जानकारी उनके परिवार के सदस्य ने दी. देव आनंद की पोती जीना नारंग ने सुनील आनंद के निधन की बात कंफर्म करते हुए एक स्टेटमेंट भी जारी किया. उन्होंने कहा कि भारी मन से हमारा परिवार सुनील आनंद के निधन पर शोक व्यक्त करता है. इस मुश्किल समय में हमें जो प्यार, दुआएं और साथ मिला है, उसके लिए हम सभी के आभारी हैं. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस कठिन समय में हमारे परिवार की प्राइवसी का सम्मान करें.देव आनंद के बेटे सुनील आनंद भी एक्टिंग कर चुके थे. बॉलीवुड लेजेंड ने खुद अपने बेटे को फिल्मों में लॉन्च किया था. साल 1984 में फिल्म आनंद और आनंद से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा।

दोबारा प्रदर्शन करेगी सीजेपी

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर दिए गए अंतरिम आदेश पर सीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया तो वो फिर से प्रोटेस्ट

शुरू कर देंगे. अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर पुलिस के हाथों स्टूडेंट्स को परेशान करना जारी रहा, तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी. सरकार को स्टूडेंट्स को टारगेट करना और उन पर विच-हंटिंग बंद करनी चाहिए। नेता सौरव दास ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने छात्रों से किया गया अपना वादा तोड़ा, तो उनके पास देशव्यापी आंदोलन दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. सौरव दास ने अपने बयान में कहा कि सीजेपी सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के पारित अंतरिम आदेश, खासतौर पर निर्देश संख्या 4, पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है।

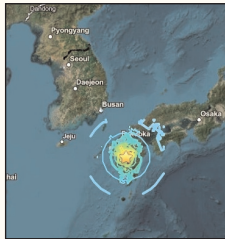
पीओके में पहले चरण के नतीजों पर विवाद

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर



में 45 विधानसभा सीटों के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक तीन चरणों में मतदान हो रहा है, पहले चरण के नतीजों में 13 सीटों में से सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने 9 और पीपीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की. केंद्र में दोनों दल गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सात सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए जांच पूरी होने तक नतीजे घोषित नहीं करने की मांग की. पार्टी नेता नैयर बुखारी ने कहा कि उनकी जीती हुई सीटें पीएमएल-एन को दे दी गईं. वहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बताया. हालांकि, मतदान के दिन हुई हिंसा ने पीपीपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और दो लोग घायल हुए. चुनाव से पहले विवादित 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी थे।

जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप



नई दिल्ली। जापान के क्यूशू द्वीप पर मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. यह भूकंप कुमामोतो क्षेत्र में आया और इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, भूकंप के बाद 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है. जापान सरकार ने कुमामोतो के अलावा नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाजाकी प्रान्तों में भी आपातकालीन भूकंप चेतावनी जारी की है. ये सभी इलाके क्यूशू द्वीप पर स्थित हैं. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है. स्थानीय प्रशासन भूकंप से हुए असर का आकलन कर रहा है और साथ ही सुनामी के खतरे भी लगातार नजर बनाए हुए है. आपातकालीन टीमें अलर्ट पर हैं और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

विभाजन विभीषिका दिवस

अपनों से बिछड़कर लाखों लोगों ने खड़ी की जिंदगी : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 1947 के विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस, संघर्ष और जिजीविषा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि विभाजन ने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया और लोगों को असहनीय पीड़ा दी, लेकिन प्रभावित लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी नई जिंदगी शुरू की और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पीएम ने भाईचारे, सद्भाव और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं, जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। यह इतिहास का वह दौर था, जिसने कई जिंदगियां तहस-नहस कर दीं। परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया और लोगों ने बहुत दुख सहा। साथ ही, इन मुश्किलों से उबरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, कठिनाइयों को सफलता में बदला और देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी दोबारा बनाई। उन्होंने विषम परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाया, मुश्किल हालात को कामयाबी में बदला और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पोस्ट में लिखा था, उनकी जीवन यात्राएं हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाती हैं। यह दिन हमारे देश में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे और हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें।



भारत 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है, ताकि 1947 में देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके।

भारत को 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। हर साल 15 अगस्त को मनाया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस किसी भी देश के लिए खुशी और गर्व का अवसर होता है। हालांकि, आजादी की इस खुशी के साथ विभाजन का गहरा दर्द भी जुड़ा था। नए आजाद भारतीय राष्ट्र के जन्म के साथ ही विभाजन की हिंसा और जासदी सामने आई, जिसने लाखों लोगों के मन पर गहरे और कभी न मिटने वाले घाव छोड़ दिए।

विभाजन के कारण मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक हुआ, जिससे लगभग 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। लाखों परिवारों को अपने पुश्तैनी गांवों, कस्बों और शहरों को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के तौर पर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कर्नाटक में आरएसएस बनाम कांग्रेस की जंग हुई तेज

शिवकुमार सरकार के नए बिल से मचा सियासी तूफान

बेंगलुरु। एक ओर राहुल गांधी लगातार आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो वहीं उनकी पार्टी के तमाम नेताओं में भी आरएसएस के खिलाफ निचले स्तर के बयान देने की होड़ लगी हुई है। इसी होड़ाहोड़ी में अपनी भी मौजूदगी दर्ज कराते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐसा फैसला किया है जोकि सीधे सीधे आरएसएस पर निशाना साधने की कार्रवाई माना जा रहा है। इस तरह कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों को लेकर कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव अब सड़क और प्रशासनिक आदेशों से निकलकर विधामसभा तक पहुंचता दिख रहा है। हम आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने Karnataka Regulation of Use of Government Premises and Public Property Bill, 2026' को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी जमीन, भवन, सड़क, पार्क, खेल मैदान और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों पर निजी कार्यक्रम, बैठक, रैली या अन्य आयोजन करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियम, दस्तावेजी प्रक्रिया और प्रशासनिक अनुमति जरूरी है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि यह व्यवस्था किसी एक दल या संगठन को निशाना बनाने के लिए नहीं है। उनका कहना है कि हर संगठन को नियमों का पालन करना होगा और सार्वजनिक



स्थानों पर कार्यक्रम अपनी इच्छा से आयोजित नहीं किए जा सकते। यही तर्क सरकार के अन्य नेताओं की ओर से भी दिया गया है।

लेकिन राजनीतिक विवाद की असली वजह विधेयक के प्रावधानों से अधिक उसका संदर्भ है। आरएसएस और भाजपा इसे संगठन की सार्वजनिक गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिश मान रहे हैं। आरएसएस की शाखाएं, बैठकें और 'संचलन' अक्सर सार्वजनिक मैदानों में होते हैं। ऐसे में रोजाना लगने वाली शाखाओं समेत हर आयोजन के लिए पूर्व अनुमति की व्यवस्था आरएसएस की नियमित गतिविधियों को प्रशासनिक स्वीकृति पर निर्भर कर सकती है। प्रस्तावित कानून में सार्वजनिक सड़कों पर होने वाले जुलूस और कार्यक्रम भी दायरे में आते हैं।

हम आपको याद दिला दें कि विवाद की जड़ अक्टूबर 2025 में दिखाई दी थी, जब राज्य सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति पर कार्यक्रमों के लिए पुलिस और राजस्व अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने का आदेश जारी किया था। इसी अवधि में चित्तापुर में आरएसएस के प्रस्तावित रूट मार्च को अनुमति नहीं मिली। उस समय भी यह सवाल उठा था कि क्या प्रशासनिक आदेश के जरिए सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है।

थोक मुद्रास्फीति जुलाई में मामूली घटकर 9.78% पर

नई दिल्ली। ईंधन एवं बिजली तथा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी के बीच थोक मुद्रास्फीति जुलाई में मामूली घटकर 9.78 प्रतिशत रह गई, जबकि जून में यह 9.87 प्रतिशत थी। सरकार के नए आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आंकड़ों के तहत पहली बार मुद्रास्फीति में मासिक आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। वार्षिक एवं उद्योग सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आंकड़े जारी करते हुए कहा, जुलाई 2026 में खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित), खाद्य वस्तुएं, बुनियादी धातुओं का विनिर्माण, गैर-खाद्य वस्तुएं, खाद्य उत्पादों का विनिर्माण तथा रसायनों एवं रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण थोक मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक रहें। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 5.44% रही।

जुलाई में खाद्य तेल का आयात 8% घटकर 14.81 लाख टन पर

नई दिल्ली। जुलाई में भारत का खाद्य तेल का आयात आठ प्रतिशत घटकर 14.81 लाख टन रह गया। उद्योग निकाय एसईए ने यह जानकारी दी। पिछले साल इसी महीने में खाद्य तेल का आयात 16.16 लाख टन था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने बयान में कहा कि जुलाई, 2026 में भारत का वनस्पति तेल (खाद्य एवं अखाद्य) आयात सालाना आधार पर सात प्रतिशत घटकर 15.25 लाख टन रह गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 16.48 लाख टन था। तेल वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 से जुलाई 2026) के पहले नौ महीनों में, वनस्पति तेल (खाद्य एवं अखाद्य) का आयात 121.50 लाख टन रहा, जबकि पिछले विपणन वर्ष की इसी अवधि में यह 116.03 लाख टन था। खाद्य तेल का कुल आयात पिछले तेल वर्ष की इसी अवधि के 113.46 लाख टन से पांच प्रतिशत बढ़कर 119.23 लाख टन हो गया।

भारतीय बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट का नया रिकॉर्ड

नईदिल्ली। भारत के बैंकिंग सिस्टम में जमा राशि तेजी से बढ़ रही है और पिछले तीन पखवाड़ों (दो हफ्ते की अवधि) में यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ट्रेडर्स का कहना है कि इसकी मुख्य वजह आरबीआई की फरिन-कॉरसी नॉन-रेसिडेंट स्कीम के तहत बैंकों में डॉलर का आना है। आरबीआई के डेटा के अनुसार, 31 जुलाई तक तीन पखवाड़ों में बैंकिंग सिस्टम में जमा राशि में कुल 11 ट्रिलियन रुपए (115.25 बिलियन डॉलर) की बढ़ोतरी हुई। 1 अप्रैल से 15 जून के बीच जमा राशि में 3.87 ट्रिलियन रुपए की शुद्ध कमी देखी गई थी। जून में, आरबीआई ने एनआरआई जमा राशि को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंटेड स्वैप विंडो की घोषणा की और त्रुटि देने वालों व सरकारी कंपनियों को सस्ता डॉलर फंड जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया।

स्टेल प्रमुख समाचार

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच आज से

गॉल। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों



की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। भारतीय बल्लेबाजों की शनिवार से यहां शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की श्रृंखला में स्पिन के खिलाफ कड़ी परीक्षा होगी और इस श्रृंखला का नतीजा मुख्य कोच गौतम गंभीर की देश के लाल गेंद क्रिकेट के प्रभारी के तौर पर भूमिका के लिए काफी अहम होगा। गंभीर के कार्यकाल में भारत सफेद गेंद (सीमित ओवरों का क्रिकेट) के क्रिकेट में लगभग अजेय टीम रहा है जिसका अंदाजा चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 विश्व कप में उसके खिताबी अभियान से लगाया जा सकता है।

मौजूदा टीम भी युवा कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में करियर के मध्य चरण में पहुंच चुके अनुभवी खिलाड़ियों और अपनी जगह पकड़ी करने को बेताब युवा खिलाड़ियों से भरी है। उसे भी ऐसी ही एक चिंगारी की जरूरत है जो शीर्ष पर वापसी के उसके सफर को गति दे सके। लेकिन इसके लिए भारत को स्पिन के इस जाल से निकलने के साथ-साथ कुछ खिलाड़ियों के खराब व्यक्तिगत दौर से बाहर निकलने की उम्मीद भी करनी होगी।

खासकर ब्रह्म पंत और ध्रुव जुरेल के लिए यह अहम समय है। जुरेल को सरफराज खान पर तरजीह मिल सकती है। इन दोनों का हालिया प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। मध्यक्रम के इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से निकलने वाले रन और श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ उनका प्रदर्शन इस टेस्ट में बेहद महत्वपूर्ण होगा। भारत की शीर्ष तीन बल्लेबाजों लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल से भी बड़ी पारियों की उम्मीद होगी। हालांकि गिल टीम की बल्लेबाजी के केंद्र में होंगे। गॉल की पिच के बेहद मुश्किल होने की उम्मीद नहीं है। मैच आगे बढ़ने के साथ इसमें स्वाभाविक टूट-फूट आने की संभावना है।

आर्थिक/वित्तिय/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सैंसेक्स 70 अंक लुढ़का निफ्टी 24366 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय बाजारों में शुक्रवार 14 अगस्त को भी बिकवाली देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। इसके चलते निवेशकों को करीब 72000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बाजार पर दबाव बनाने का काम फार्मा और मेटल सेक्टर के शेयरों ने किया। निफ्टी फार्मा और मेटल इंडेक्स में 0.70-0.90 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 29.85 अंकों की गिरावट के साथ 24366 पर बंद हुआ, जोकि कारोबारी सेशन में 24296 तक फिसला था। बीएसई सेंसेक्स 70.71 अंकों की गिरावट के साथ 78009 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में टॉप लूजर में टाटा मोटर्स शामिल रहा, जो 4.3 फीसदी गिरकर बंद हुआ। जियो फाइनेंशियल्स 2.56 फीसदी, एशियन पेंट्स 2.15 फीसदी और हिंडालको 1.6 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए।

डॉ जयंती लाल भण्डारी

इन दिनों देश में बढ़ती महंगाई, कमजोर मानसून और अमेरिका के बहुआयामी टैरिफ- वीजा संबंधी नई मुश्किलों पर प्रकाशित हो रही रिपोर्टें भारतीय अर्थव्यवस्था की चिंताएं बढ़ा रही हैं। पांच अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में महंगाई, आर्थिक स्थिति और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से जुड़ी तस्वीर पेश की है।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान पांच प्रतिशत कर दिया है। खाद्य वस्तुओं के क्षेत्र में महंगाई में वृद्धि के संकेत हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान 6.17 प्रतिशत कर दिया गया है। खास तौर से रेपो रेट (वह ब्याज दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक

से कर्ज लेते हैं) को लगातार चौथी बार 5.25 प्रतिशत के स्तर पर यथावत रखा गया है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में मानसून, अल नीनो और पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से खाने-पीने के वस्तुएं और ईंधन महंगे हो सकते हैं। इस समय प। एशिया संकट और अमेरिकी प्रशासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, माल ढुलाई संकट और व्यापारिक बाधाओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में प्रस्तुत ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक प। एशिया में बढ़ते तनाव व व्यापारिक अनिश्चितता के चलते जुलाई 2026 में भारत की आर्थिक गतिविधियां पिछले चार वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं।



इस समय अमेरिका से भी भारत के लिए टैरिफ व वीजा परिदृश्य नई चुनौतियों के रूप में दिख रहा है। 25 जुलाई को अमेरिकी सीनेट में एच-1बी वीजा पर तीन साल तक रोक लगाने संबंधी एक नया और बेहद सख्त विधेयक पेश किया गया है। 24 जुलाई से प्रतियोगिता के लिए रणनीतिपूर्वक

तरीके से 200 प्रतिशत तक टैरिफ का ऐलान किया गया है। हालांकि इस समय भारत आपूर्ति चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से बेहतर स्थिति में है, फिर भी चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर को सात प्रतिशत तक ले जाने के लिए रणनीतिपूर्वक

नए आर्थिक उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। निस्संदेह इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और घरेलू आर्थिक मुश्किलों के बीच अर्थव्यवस्था को गतिशील रखना और विकास दर बढ़ाना चुनौती है।केंद्रीय बैंक को अब महंगाई को नियंत्रण में रखने के साथ-साथ विकास की गति को थमने से बचना होगा। वैश्विक संकट के समय निजी निवेश में सुस्ती आना स्वाभाविक है।

ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए सरकार को अपने पूंजीगत व्यय को लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कारगर बनाना होगा। भारत को अपनी निवेश नीतियों को और अधिक सरल बनाकर वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना होगा। अब बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों(एफटीए) को भी ढाल बनाना होगा।

चरोदा के पीपी यार्ड में सीबीआई की दबिश, रेलवे अधिकारी से पूछताछ

वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के खिलाफ बिल पास करने के एवज में मोटी रकम मांगने की शिकायत

दुर्ग। रायपुर रेल मंडल के भिलाई स्थित चरोदा पीपी यार्ड में छद्म ने बड़ी कार्रवाई की है. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के खिलाफ बिल पास करने के एवज में मोटी रकम मांगने की शिकायत मिलने के बाद छद्म की टीम ने गुरुवार देर रात चरोदा स्थित पीपी यार्ड में दबिश दी। सीबीआई की टीम सीनियर डीएमई अनमोल उड़के से पूछताछ कर रही है, साथ ही उनके कार्यालय में दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार सीनियर डीएमई अनमोल उड़के के खिलाफ दिल्ली छद्म को शिकायत मिली थी। सीनियर डीएमई के रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर के रनिंग बिल पास करने के एवज में मोटी रकम मांगने की शिकायत छद्म से की गई थी। इस शिकायत के बाद गुरुवार देर रात छद्म भिलाई के चरोदा पहुंची। फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है।

रेलवे कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार छद्म के 8 अधिकारियों की टीम दिल्ली और छत्तीसगढ़ पासिंग गाड़ियों में चरोदा पीपी यार्ड पहुंची है। सीबीआई के 10 से 12 सदस्य की टीम सीनियर डीएमई के ऑफिस पहुंचकर पूछताछ के साथ दस्तावेज



खंगाल रही है।

सीबीआई ने पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा हुआ है। पीपी यार्ड के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और किसी भी रेल अधिकारी या कर्मचारी को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल सीबीआई की ओर से अधिकृत जानकारी नहीं दी है टीम की जांच जारी है। आपको बता दें कि पीपी यार्ड में

रेलवे वैगन के मेंटेनेंस का काम किया जाता है। यहां पहले भी इसी तरह वर्ष 2023 में कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लेने के आरोप में छद्म ने दबिश दी थी।एक बार फिर भिलाई का पीपी यार्ड छद्म की रडार में है। कुछ दिनों पहले भी सीबीआई ने रायपुर रेल मंडल में खेल कोटे में नौकरी दिलाने के नाम पर रकम एंठने के मामले में दबिश दी थी।

16 अगस्त से पहले ई-केवाईसी नहीं कराया तो गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद

कोरबा। कोरबा जिले में करीब 5 लाख एलपीजी के गैस कनेक्शन हैं। जिनमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी शामिल हैं। अलग-अलग गैस वितरकों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 15 से 20 फीसदी गैस कनेक्शन धारकों ने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है। दरअसल बार बार की मोहलत के बाद भी बड़ी संख्या में लोग ई-केवाईसी प्रक्रिया से दूर हैं। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ कर दिया है कि 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लोगों के सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होगी। सप्सिडी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ई-केवाईसी के लिए जारी निर्देश के अनुसार एलपीजी ग्राहकों के सत्यापन कराने पर ही सिलेंडरों की डिलीवरी होगी। सत्यापन नहीं कराने कराने वाले ग्राहकों के खाते में एलपीजी की सप्सिडी भी जमा नहीं होगी। ऑनलाइन गैस की बुकिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, ऐसे कनेक्शन कंपनी के अधिकारियों के संदेह के दायरे में भी हैं। अफसरों का मानना है कि इन कनेक्शनों में दूसरे जिले या राज्यों में जाने वाले, जिनके नाम से कनेक्शन हैं, उनकी मृत्यु हो जाने या एक ही नाम से ज्यादा कनेक्शन लेने वाले लोग शामिल हैं, इसलिए अब समय-सीमा तय कर दी गई है। 16 अगस्त के बाद ऐसे कनेक्शनों का फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ सत्यापन किया जाएगा, जिसमें गड़बड़ी मिलेगी, उन कनेक्शनों को रद्द कर दिया जाएगा। यही वजह है कि पेट्रोलियम कंपनियां लोगों से बार-बार सत्यापन कराने को कह रही हैं।

उपभोक्ता अपनी सुविधा के मुताबिक संबंधित गैस एजेंसी में जाकर आधार और गैस कनेक्शन की जानकारी के साथ ई-केवाईसी करा सकते हैं। सामान्य उपभोक्ता हों या फिर उज्ज्वला कनेक्शनधारी, सभी को सत्यापन कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। 16 अगस्त तक आखिरी तारीख है। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी भी कराई गई है। घर घर जाकर भी जानकारी दी गई है। प्रशासन भी जुटा है। प्रक्रिया जारी है।

छत्तीसगढ़	प्रमुख समाचार	तिरंगे के प्रति सामान की भावना से निकली तिरंगा यात्रा
		सरगुजा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंह देव, कलेक्टर अजीत वसंत और एसपी राजेश अग्रवाल भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत के लिए जिला प्रशासन ने उस स्कूल का चयन किया जो देश की आजादी का साक्षी रहा है। आजादी के पहले से विद्वमान मल्टीपरपज स्कूल से यात्रा शुरू की गई और अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में आकर यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में स्वच्छता दीदी, स्कूली बच्चे, स्काउट एंड गाइड्स व एनसीसी के बच्चो ने भी सहभागिता निभाई। जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा विभाग और नगर निगम के सामूहिक प्रयास से रैली का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग देश भक्ति गीतों और स्काउट एंड गाइड के बैंड की थीम पर हाथों में तिरंगा लेकर चलते रहे। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा राष्ट्र के प्रति प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था।

अमरकंटक से पंडरिया पहुंची विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा

कवर्धा। मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पवित्र जल लेकर निकली पंडरिया विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा पांचवें दिन उनके विधानसभा क्षेत्र पंडरिया पहुंची। यात्रा के पंडरिया पहुंचने पर जगह-जगह लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने विधायक भावना बोहरा को फोन कर हालचाल जाना और सभी कांवड़ियों को इस पवित्र यात्रा की बधाई शुभकामनाएं दी। विधायक भावना बोहरा ने अपनी कांवड़ यात्रा के अनुभव ईटीवी भारत से साझा किए। उन्होंने बताया कि सोमवार को अमरकंटक से सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ पवित्र जल लेकर यात्रा की शुरुआत की गई थी। यात्रा के दौरान घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच से होकर गुजरना पड़ा। कई स्थानों पर रास्ता कठिन था। किसी ने इसे सशक्तिकरण का वास्तविक रूप देकर कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने बताया कि रात के समय यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले सहयोगियों और ग्रामीणों के घरों में रुककर विश्राम किया।

आज इनमें से कई महिलाएं सामाजिक संगठनों के साथ काम कर रही हैं, नई आजीविका तलाश रही हैं और उन अवसरों को हासिल कर रही हैं, जो कभी उनके लिए दूर की बात थे। रैंप पर उनका आत्मविश्वास इस बात का संकेत है कि पुनर्वास केवल हथियार छीन लेने का नाम नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का रास्ता खोलने की प्रक्रिया है।

इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने भी इसे बस्तर के बदलते चेहरे की असाधारण तस्वीर बताया। कई यूजर ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक ऐसी तस्वीर की कल्पना करना भी कठिन था। किसी ने इसे सशक्तिकरण का वास्तविक रूप बताया तो किसी ने सवाल उठाया कि ऐसी कहानियों को व्यापक प्रचार क्यों नहीं मिलता। दरअसल, रैंप पर चलती ये महिलाएं उस बदलाव की प्रतिनिधि हैं, जो दशकों तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में धीरे-धीरे जमीन पर आकार ले रहा है।

बस्तर में बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर खेल के मैदानों से भी सामने आई है। बस्तर ओलंपिक 2025 में

आईपीएस पर 1 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप

आईजी ने कहा- जांच प्रभावित न हो इसलिए एएसआई और आरक्षक लाइन अटैच, विवेचना जारी

अंबिकापुर। अंबिकापुर साइबर थाने में दर्ज एक बड़े साइबर फ्रॉड केस ने पूरे देश में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल इस मामले की जांच की जिम्मेदारी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल को दी गई थी। मामले में अलग-अलग राज्यों से अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन शिकायतकर्ता ने आईपीएस राहुल बंसल पर एक करोड़ रुपये रिश्त मांगने का आरोप लगाया है, जिसने हलचल बढ़ा दी है। शिकायत के बाद मामला सीबीआई और न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन अब सरगुजा रेंज आईजी दीपक झा ने आरोपों को लेकर पुलिस का पक्ष साफ किया है। आईजी के मुताबिक अब तक की जांच में राहुल बंसल के खिलाफ रिश्त मांगने या शिकायत में उनकी संलिप्तता का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि वायरल वीडियो, ऑडियो और पुलिसकर्मीयों के मोबाइल नंबरों की जांच अभी जारी है। वहीं इस मामले में जांच प्रभावित न हो इस कारण साइबर थाने में पदस्थ एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को आईजी ने पुलिस लाइन अटैच किया है। जांच में जिसके



खिलाफ जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया तय होगी।

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा निवासी आकाश कुमार पर अंबिकापुर के साइबर रेंज थाने में ठगी का मामला दर्ज है। मामला 20.15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी से जुड़ा है। आकाश ने सीबीआई दिल्ली कोर्ट में परिवार दायर कर बताया कि ठगी के केस की जांच के दौरान कार्रवाई को प्रभावित करने अंबिकापुर सीएसपी (ट्रेनी आईपीएस) राहुल बंसल ने एक करोड़ की मांग की।शिकायतकर्ता आकाश ने दावा किया कि रिश्त की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए आईपीएस तक पहुंचाई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक

अंशुल शर्मा ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। बातचीत का स्क्रीन शॉट और ऑडियो रिकॉर्ड भी उनके पास हैं। पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने पूर्व में सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर घटनाक्रम की जांच की मांग की थी, लेकिन शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पीडित ने शिकायत की कॉपी भी कोर्ट में पेश की है। कार्रवाई नहीं होने से दुखी शिकायतकर्ता ने दिल्ली सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में धारा 175 3, के तहत परिवार दायर किया है। साथ ही आईपीएस राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण राठौर, आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए, भारतीय न्याय संहिता बियनए 2023 की धारा 308 और 351 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। इस शिकायत पर सीबीआई कोर्ट ने आईपीएस समेत तीनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

शिकायत में प्रशिक्षु आईपीएस राहुल बंसल की कथित भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन सरगुजा रेंज ड्रग दीपक झा के मुताबिक शिकायत में जिन मोबाइल नंबरों का जिक्र है, वे राहुल बंसल के नंबर नहीं हैं।

तैदूपता खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला



नहीं होता।

हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि 1964 का कानून तैदूपता के संग्रहण, खरीद, परिवहन और व्यापार को नियंत्रित करता है, जबकि Biological Diversity Act, 2002 का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, जैव संसाधनों का सतत उपयोग और उनके व्यावसायिक उपयोग से होने वाले लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। दोनों कानून अलग-अलग लेकिन पूरक क्षेत्रों में काम करते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी नीलामी के जरिए तैदूपता खरीदने मात्र से खरीदार एबीएस की वैधानिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। तैदूपता जैव संसाधन है और उसका व्यावसायिक उपयोग ऋद्धश्रद्धश्रद्धश्रद्ध श्रद्धादृद्धदृद्ध4 दृद्ध के दायरे में आता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड को कानून के तहत निर्धारित राशि की वसूली का अधिकार है।

फैसले में Forest Rights Act, 2006 का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने कहा कि तैदूपता फॉरेस्ट प्रोड्यूस में शामिल है और कानून वनवासी समुदायों को इसके संग्रहण, उपयोग और निपटान से संबंधित अधिकार प्रदान करता है।

कारोबारियों को देना होगा 2 प्रतिशत एबीएस शुल्क, सभी याचिकाएं स्वारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तैदूपता फॉरेस्ट लॉट की सरकारी नीलामी में खरीद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कारोबारियों से 2 प्रतिशत Access and Benefit Sharing (ABS) राशि की वसूली के मामले में ये सुनवाई की। इसके बाद राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से जारी आदेश को वैध मानते हुए इस संबंध में दायर सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। फैसला 13 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद ने सुनाया। मामला राज्य जैव विविधता बोर्ड के 24 जनवरी 2023 के आदेश और 25 जनवरी

2023 के एक लेटर से जुड़ा था।

इन निर्देशों के जरिए तैदूपता फॉरेस्ट लॉट के सफल खरीदारों से खरीद मूल्य का 2 प्रतिशत ऋके रूप में वसूलने की व्यवस्था की गई थी। कारोबारियों ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्होंने तैदूपता सीधे वनवासियों या संग्राहकों से नहीं खरीदा, बल्कि राज्य की वैधानिक व्यवस्था के तहत सार्वजनिक नीलामी में फॉरेस्ट लॉट खरीदे हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि तैदूपता की खरीद और व्यापार पहले से ही छत्तीसगढ़ तैदूपता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के तहत नियंत्रित है। राज्य सरकार और उसकी अधिकृत एजेंसियां संग्राहकों से तैदूपता खरीदती हैं और बाद में फॉरेस्ट लॉट की नीलामी की जाती है। ऐसे में कारोबारियों का प्राथमिक संग्राहकों से कोई सीधा लेन-देन

राजनांदगांव में करोड़ो रूपये से बने उद्यानों का खस्ता हाल

राजनांदगांव। शहर वासियों को बेहतर उद्यान की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए भले ही ननि विशेष प्रयास कर रहा हो, लेकिन स्थिति इसके विपरीत ही देखने को मिल रही है। शहर में करोड़ों रुपये की लागत से विकसित किए गए उद्यानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। रखरखाव के अभाव में कई उद्यान उजड़ने लगे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ गई है। ध्यान दिलाए जाने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। उद्यानों में लगाए गए फूल और सजावटी पौधे भी धीरे-धीरे गायब होते जा रहे हैं। हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किए गए इन उद्यानों में एक सूखे पौधे और खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुंदरता पूरी तरह से गायब होती नजर आ रही स्थिति यह है कि कई उद्यानों के परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नियमित साफ-सफाई नहीं होने से लोगों ने उद्यानों में जाना भी कम कर दिया है। सुबह और शाम टहलने आने वाले लोगों ने भी व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

लीज नवीनीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

भिलाईनगर। भिलाई नगर निगम स्थित दुकानों के वार्षिक किराया नामांतरण शुल्क और लीज नवीनीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुकान के विक्रय, हस्तांतरण पर निकाय को नामांतरण शुल्क देना होगा। जनसंख्या के आधार पर दरें तय की गई हैं। 3 लाख से कम जनसंख्या 20,000 रुपए, 3 से 10 लाख जनसंख्या 25,000 रुपए व 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर नामांतरण शुल्क 30,000 रुपए किया गया है। आवंटित की मृत्यु होने की दशा में वारिसातों के पक्ष में नामांतरण के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। नामांतरण के लिए आवंटित को लीज डीएड के 2 वर्ष बाद संयुक्त आवेदन, एक-एक शुल्क और अंखबार में 30 दिन का दावा- आपत्ति प्रकाशन कराना अनिवार्य होगा। किराये और लीज के नियम वार्षिक किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का प्रतिशत के आधार पर तय होगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में यह 7.20ब है। किराये में वृद्धि हर 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये में 5ब चक्रवृद्धि से वृद्धि का प्रावधान है।

नशे की गिरफ्त में आए मासूम को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती

राजनांदगांव। हाई स्कूल ग्राउंड में बच्चों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस के सामने पहुंचे 10 वर्षीय बालक की कहानी ने पुलिस अधिकारियों को भी भावुक कर दिया। कम उम्र में ही पिता को खो चुके इस बच्चे की मां भी उसे छोड़कर चली गई थी। माता-पिता का साथ उठने के बाद बच्चा अकेलेपन और नशे की गिरफ्त में चला गया था, जिसे स्क अंकिता शर्मा के निर्देश पर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया। दरअसल, 9 अगस्त की शाम हाई स्कूल ग्राउंड में बच्चों के बीच विवाद हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद बालक को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने जब उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। बताया गया कि कई साल पहले एक हत्या की घटना में बालक ने अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद मां के चले जाने से वह पूरी तरह अकेला पड़ गया। देखरेख और सहारे के अभाव में उसने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया।

मोदी ने माहौल ही बदल डाला, रेड कॉरिडोर से रेड कार्पेट पर रैंप वॉक करने लगीं पूर्व नक्सली महिलाएं

नौरज कुमार दुवे

रेड कॉरिडोर पर चलने वाले कदम अब रेड कार्पेट पर अपने जलवे बिखेर रहे हैं। कभी नक्सलियों की साथी रहने के दौरान हाथों में बंदूक थामकर बस्तर के घने जंगलों में भटकने वाली महिलाएं अब उसी आत्मविश्वास के साथ रैंप पर चल रही हैं, जहां उनके स्वागत में गोलियों की आवाज नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। रायपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित ट्राइबल फैशन शो में पूर्व महिला माओवादियों ने हाथ से बुने परिधानों में रैंप वॉक कर एक ऐसी तस्वीर पेश की, जिसकी कुछ साल पहले कल्पना भी मुश्किल थी। यह सिर्फ फैशन शो नहीं था, बल्कि बंदूक से मुख्यधारा, हिंसा से विकास और भय से आत्मविश्वास तक बस्तर की बदलती कहानी का जीवंत प्रतीक था।

कभी बस्तर के जंगलों में हथियार उठाकर चलने वाली इन महिलाओं ने आत्मसमर्पण के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ा और समाज में लौटने का फैसला किया।

आज इनमें से कई महिलाएं सामाजिक संगठनों के साथ काम कर रही हैं, नई आजीविका तलाश रही हैं और उन अवसरों को हासिल कर रही हैं, जो कभी उनके लिए दूर की बात थे। रैंप पर उनका आत्मविश्वास इस बात का संकेत है कि पुनर्वास केवल हथियार छीन लेने का नाम नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का रास्ता खोलने की प्रक्रिया है।

इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने भी इसे बस्तर के बदलते चेहरे की असाधारण तस्वीर बताया। कई यूजर ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक ऐसी तस्वीर की कल्पना करना भी कठिन था। किसी ने इसे सशक्तिकरण का वास्तविक रूप बताया तो किसी ने सवाल उठाया कि ऐसी कहानियों को व्यापक प्रचार क्यों नहीं मिलता। दरअसल, रैंप पर चलती ये महिलाएं उस बदलाव की प्रतिनिधि हैं, जो दशकों तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में धीरे-धीरे जमीन पर आकार ले रहा है।

बस्तर में बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर खेल के मैदानों से भी सामने आई है। बस्तर ओलंपिक 2025 में



3.91 लाख से अधिक खिलाड़ियों का पंजीयन हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण यह रहा कि 700 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सली और हिंसा से प्रभावित ग्रामीण ‘नियो बात’ यानी ‘नया रास्ता’ टीम के तहत खेलों में शामिल हुए। महिलाओं और बेटियों की भागीदारी भी लगभग तीन गुना बढ़ी। यानी जिन इलाकों में कभी बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब खेलों की तालियां सुनाई दे रही हैं। शिक्षा के मोर्चे पर भी बदलाव साफ दिखाई देता है। माओवादियों द्वारा ध्वस्त या बंद करए गए कई स्कूल फिर खुले हैं और जंगलों के बीच बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हुई है। आदिवासी युवाओं

को बेहतर अवसर देने के लिए 259 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, 46 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार अब विकास को बस्तर के आखिरी छोर तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। ‘नियद नेल्लानार’ योजना के तहत सुरक्षा बलों के कैंपों को ‘सेवा डेरा’ के रूप में इस्तेमाल कर ग्रामीणों तक राशन, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। ‘हर गांव रोशन’ जैसी पहलों के जरिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व जैसे दुर्गम इलाकों के 70 से अधिक गांवों तक पहली बार बिजली और सोलर लाइटिंग पहुंची है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि से आदिवासी गांवों में पक्के मकान और बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है।

साथ ही कनेक्टिविटी भी इस बदलाव की रीढ़ बन रही है। बस्तर के दुर्गम इलाकों में 11 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों और 1,300 से ज्यादा मोबाइल टावरों का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण बाजारों, प्रशासन और देश-दुनिया से जुड़ रहे हैं। उधर, माओवाद के कमजोर पड़ने के बाद सुरक्षा बल अब जंगलों में छिपे आईईडी

को भी नष्ट कर रहे हैं और ‘आईईडी मुक्त पंचायत’ की दिशा में काम हो रहा है। इस बदलते माहौल की पुष्टि राजनीतिक स्तर पर भी हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय योजनाओं के मानकों में विशेष छूट की मांग की है। उनका कहना है कि चार-पांच दशकों के बाद बस्तर माओवाद के प्रभाव से बाहर निकलने की स्थिति में पहुंचा है, लेकिन दूर-दराज बिखरी आबादी के कारण सामान्य जनसंख्या आधारित नियमों के तहत सड़क निर्माण में दिक्कत आती है। अब चुनौती है कि शांति को स्थायी विकास में बदला जाय। सबसे प्रतीकात्मक बदलाव तिरंगे को लेकर है। बस्तर संभाग के 92 से अधिक ऐसे सुदूर गांवों में स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया गया है। साथ ही पुनर्वास नीति 2025 के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को घर, जमीन, मासिक सहायता और रोजगार के अवसर देकर मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन की राह दी जा रही है।



स्वतंत्रता से सुरक्षा तक, विरासत से विकास तक, नई पहचान गढ़ रहा छत्तीसगढ़

80वें स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त 2026
की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं...



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से
जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें।



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सुशासन से समृद्धि की ओर...

संवाद-48753/161